

पाने का हक है। उस न्याय से वहाँ के सैकड़ों-हजारों लोगों को आज वंचित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायपालिका के निर्णय कार्यान्वित नहीं हो रहे हों तो फिर केन्द्र सरकार अगर नहीं देखे, तो संविधान के पालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भिन्न राज्य सरकारों की होती है और कितनी सरकार की मुख्य रूप से होती है। भारत के राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा और संरक्षा की शपथ लेते हैं और बिहार में संविधान की पूरे तौर पर अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है और पूरे राज्य में अराजकता का माहौल और असुरक्षा का माहौल बन गया है। मुख्य रूप से जो टिप्पणी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश ने की है, उस टिप्पणी को भारत सरकार गंभीरता से ले और कोई कारगर उपाय तत्काल निश्चालने पर गंभीरता से विचार करे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : जो मिथ जी ने बात उठाई है, वह गंभीर है और उन्होंने वस्तु-स्थिति का ही चित्रण किया है। मैं अपने आपको, अपने दल को उनकी बात से सम्बद्ध करता हूँ। लेकिन मुख्य चीज यह है कि जब न्यायाधीश भी यह कहें कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और आम आदमी भी यह अनुभव करता है कि जैसे वहाँ कोई सरकार नहीं, केवल जंगल राज है, तो उचित ही कहा गया। मैं भी उनसे आवाज मिलाता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर संवैधानिक सरकार है या नहीं।

उपसभाध्यक्ष (संघ सचिवे रजी) : आप एसोशिएट कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर नहीं हैं तो गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को, मैं यह कहूँगा कि प्रधान मंत्री बाहर जाने वाले हैं, उनको श्रीमन् प्रधान देकर कोई न कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

Setting up of more public sector factories in Bihar

श्री नागमणि : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस तरह से केन्द्र ने शुरू से बिहार को नेग्लेक्ट किया है, उसकी ओर मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1962 के बाद बिहार में पब्लिक सेक्टर में एक भी बड़ा कारखाना नहीं खोला गया, जबकि पूरा देश जानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ और रॉमैटीरियल है, खासकर के यह जो प्लामू और चित्तौड़ जिला का इलाका है, 9-10 खनिज पदार्थ वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन 30 वर्षों के दरम्यान बिहार में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, जिसके चलते पूरे बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, नेक्सलाइट और आतंकवादी बनने पर मजबूर हैं। हम आपको इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि आज बिहार का नौजवान यह सुनना नहीं चाहता है कि बिहार को केन्द्र नेग्लेक्ट करे और बिहार के लोग सुनते रहेंगे। हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं और महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार में केन्द्रीय विश्व विद्यालय की मांग वर्षों से होती रही। बिहार से छोटा राज्य-आसाम है, इसी पिछले सेशन में दो-दो केन्द्रीय विश्व विद्यालय दिए गए। लेकिन बिहार में एक भी केन्द्रीय विश्व विद्यालय नहीं दिया गया है। *

उपसभाध्यक्ष (संघ सचिवे रजी) : उपाय आपका जो विशेष उल्लेख है उससे ही सीमित रखें। दूसरे, जो भी यहाँ बातें कही जाती हैं वह संविधान के ढाँचे में कही जाती हैं। मैं इस पटल को राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूँगा कि आप केन्द्रीय सरकार के खिलाफ इस प्रकार की बात कहें। जो भी इन्होंने कहा है, जिसका संदर्भ मैंने अभी लिया है, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा। आप स्पेशल सेशन तक ही अपने को सीमित रखें।

*Not recorded.

श्री नागभणि: महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मैंने जो कहा कि 1962 के बाद से बिहार में एक भी बड़ी इण्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर में नहीं दी गई है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्र की यह नीति सही है? और अगर वह के मौजवान लोग... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिद्वे रजी): अब आप समाप्त करें। आपकी बात हो गई।

* [اب سید ان ہو کہش (شہی سے - سبط رضی : اب اب سماپٹ کریں - اپنی بات دو گئی -]

श्री नागभणि: मैं यह कह रहा था कि बिहार के लोग....*

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिद्वे रजी): देखिए चेयर की रुलिंग के खिलाफ मत बोलिए... (व्यवधान) कृपया बैठिए... (व्यवधान) देखिए, माननीय सदस्य इस सदन के नए सदस्य हैं इसलिए यहाँ के अदब और तहजीब से मैं समझता हूँ कि वे पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात जो संविधान के ढाँचे के बाहर हो, आप इस पटल पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने इस पर अपनी रुलिंग दे दी है। अब कृपया उस बात को आप पुनः रिपीट मत करें। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका समय हो गया है... (व्यवधान) आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः इन्होंने जो उस तरह की बातें कहीं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएंगी।

श्री भूपिन्दर सिंह मान: वे तो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। रामदास अग्रवाल जी, आप बोलिए।

*[No] recorded.

\$(O)Translation in Arabic Script,

आप सजाओ इच्छित, देखिये - जैसी की रोड लॉक के फलान मदत लो लें... "मि उधलत"

कमिया चिपुठिये... मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

मि उधलत मि उधलत मि उधलत मि उधलत

Heavy losses in Public Sector Banks

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक आफ इंडिया की जो रिपोर्ट हमारे बैंकों के कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत की गई है, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस समय किया गया था, यह विचार रखा गया था इन सदनों में कि चूंकि बैंक एपिथियोटली काम नहीं कर रहे हैं या शायद कहीं शोषण भी करते हैं, इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि आम आदमी को उसका लाभ भी मिल सके और इतना सारा जो रुपया केन्द्रीय-